छत्तीसगढ गैर कृषि क्षेत्र में टसर कोसा उत्पादन एवं इसके द्वारा रोजगार की संभावनाएँ
(एक विश्लेषणात्मक अध्ययन)

***डॉ मनीषा दुबे**

आचार्य एवं विभागाध्यक्ष

**** नसीमा बेगम अंसारी**

शोध छात्रा

19 वीं शताब्दी के दौरान गैर कृषि क्षेत्रो में रोजगार की वृद्धि दर काफी संतोषजनक रही। रोजगार उपलब्ध कराने में गैर कृषि क्षेत्रों की बेजोड़ सहभागिता को आर्थिक सुधारों के एक महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव के रूप में देखा जा रहा है, किन्तु स्पष्ट रूप से कहा जाए तो पिछले कुछ वर्षो में कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन काफी दुखद रहा। अपने हाल पर बेहाल कृषि कृषको के लिए कांटो भरी राह साबित हो रही है, जिसने कृषकों का रूख गैर कृषि क्षेत्रो की ओर मोड़ा जिसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के नजरिये से अच्छा संकेत मान कर एक क्रांति के श्री गणेश के रूप में देखा जा रहा है।

छत्तीसगढ़ के संदर्भ में उपर्युक्त स्थिति का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि राष्ट्रीय औसत से अधिक छत्तीसगढ़ की **76.76%**[1] ग्रामीण आबादी मे से **80%**[2] आबादी प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से अपनी जीविका हेतु कृषि पर आश्रित है, किंतु प्रदेश में सिंचित क्षेत्र मात्र **30 %**[3] है, परिणामतः एक फसल के अलावा दो फसली उत्पादन मात्र कल्पना है। कृषको की मौसम पर निर्भरता, उनकी आय की अनिश्चितता का कारण है । घाटे का सौदा साबित हो रही कृषि हेतु पर्याप्त सुविधाओं के अभाव एवं राज्य G.D.P. में कृषि के गिरते ग्राफ ने कृषि उत्पादन की लागत को अप्रत्याशित रूप से बढ़ा दिया है। शासन की नीतियो एवं सुधारो के फलस्वरूप किसानो का रूख गैर कृषि क्षेत्रो की ओर हुआ जिसमें मत्स्य पालन, डेयरी फार्म, बागवानी, बीड़ी एवं रेशम उद्योग प्रमुख रूप से शामिल है।

अर्थशास्त्र विभाग, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय (छ.ग.)

1. आर्थिक सर्वेक्षण, छ0ग0 शासन (2013) कृषि एवं संबंध सेवाएं पृष्ठ–38
2. http://indiafactores.in/indiacensus-2011/urbanruralpopulation.
3. आर्थिक सर्वेक्षण, छ0ग0 शासन (2013) कृषि एवं संबंध सेवाएं पृष्ठ–38

किंतु प्रस्तुत शोध पत्र जिसके अध्ययन का क्षेत्र छत्तीसगढ़ है, में आधार भूत समस्या यह है कि यह राज्य आदिवासी बाहुल्य (**32.5** %)[4] है, एवं वनसंपदा राष्ट्रीय औसत से अधिक **42** %[5] है।, तो वही दूसरी ओर राज्य के **76** %[6] कृषक लघु एवं सीमांत श्रेणी में शामिल है एवं ग्रामीण गरीबी अधिकतम **49.2** %[7] है। वस्तु स्थिति यह हैं कि वन संसाधनों कि पर्याप्तता, कृषि की खस्ताहाल हालत एवं भौगोलिक, जनांकिकी संरचना को देखते हुए प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में रेशम उद्योग प्राचीन काल से महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता रहा है। रेशम उत्पादन संबंधी गतिविधियां वन आधारित एवं कृषि के सहायक व्यवसाय के रूप में संचालित होने वाली है, जिसके अंतर्गत न्यून लागत, अधिक उत्पादन के साथ, उत्पादन का प्रत्येक स्तर पूर्णतया श्रम आधारित है।

भारत में **''छत्तीसगढ़ को रेशम युग के इतिहास की अनोखी कर्म भूमि''**[8] माना जाता है। प्राचीन काल से ही रेशम उत्पादन संबंधी गतिविधियां प्रदेश के आदिवासियों की अनुपम कला एवं संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। राज्य में उद्योग हेतु अनुकूल दशाओ के रूप में मौसम की अनुकूलता, ग्रामीण एवं आदिवासी जनसंख्या की बहुलता एवं पिछड़ी कृषि दशा ने रेशम उद्योग को ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि के सहायक व्यवसाय के रूप में स्थापित किया है। छत्तीसगढ़ को रेशम की ज्ञात वाणिज्यिक किस्मों में से तीन किस्मों टसर, शहतूती एवं ईरी रेशम उत्पादन करने का गौरव प्राप्त है। जिसमें से टसर रेशम का उत्पादन प्रमुख है। भारत के कुल टसर रेशम उत्पादन में योगदान की दृष्टि से झारखंड का स्थान प्रथम है एवं छत्तीसगढ़ की स्थिति **22.38**%[9] के साथ द्वितीय पायदान पर है।

रेशम उत्पादन हेतु प्रयुक्त प्रक्षेत्र में कुल 4368.50 हेक्टेयर वन क्षेत्र के अंतर्गत, 9787 हेक्टेयर रेशम परियोजना के अंतर्गत, 2973 हेक्टेयर पौधरोपण युक्त क्षेत्र उपलब्ध है।

जिसमें से 11649 हेक्टेयर क्षेत्र (रेशम उत्पादन हेतु कुल क्रियाशील क्षेत्र का 68%) पर टसर रेशम का उत्पादन (पालित एवं नैसर्गिक रूप से) किया जा रहा है।[10]

4. आर्थिक सर्वेक्षण, छत्तीसगढ़ शासन (2013) जनसंख्या पृष्ठ–4
5. आर्थिक सर्वेक्षण, छत्तीसगढ़ शासन (2013) वानिकी पृष्ठ–67

ज्ञातव्य हो कि प्रदेश के कुल रेशम उत्पादन में टसर रेशम का हिस्सा **95** %[11] है। टसर रेशम, रेशम की एक उत्कृष्ठ किस्म में शामिल है। भारत के कुल टसर रेशम उत्पादन में एक तिहाई हिस्से की पूर्ति किए जाने के बावजूद छत्तीसगढ़ में रेशम उद्योग की गणना विकसित उद्योगो में न कि जा कर पिछड़े उद्योगो में की जाती है, कारण उद्योग की कुछ विशेष समस्याएं, जिसने न केवल टसर रेशम उत्पादन को सदैव लक्ष्य से कम रखा है, बल्कि संलग्न हितग्राहियों की आय काफी अनियमित एवं न्यून भी रही है, जो कि विचारणीय है। परिणामतः प्रदेश के गैर कृषि क्षेत्रो में रोजगार सृजन की दृष्टि से रेशम उद्योग कि सहभागिता काफी सीमित रही हैं । अतः प्रस्तुत शोध का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ के गैर कृषि क्षेत्रो में रोजगार स्थिति का अध्ययन करना तथा इस संदर्भ में टसर कोसा उत्पादन द्वारा रोजगार की संभावनाओं का मूल्यांकन कर उद्योग के पिछड़े एवं अविकसित होने के कारणों को रेखाकिंत करना है।

शोध की सार्थकता :–

राष्ट्रीय औसत से अधिक ग्रामीण आबादी का निवास छत्तीसगढ़ में है, किन्तु निम्न सिंचाई सुविधा एवं सीमांत कृषको की अधिकता के कारण कृषि घाटे का सौदा साबित हो रही है।, परिणामतः राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता, प्रवास जैसी गंभीर समस्याएं व्यापक स्तर पर मौजूद है। स्वाभाविक रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गैर कृषि क्षेत्रों का महत्व बढ़ जाता है जिनके अंतर्गत बागवानी, मत्स्यपालन, डेयरी फार्म एवं रेशम उत्पादन प्रमुख है। कुटीर उद्योग की श्रेणी का रेशम उद्योग प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रो में कृषि के सहायक व्यवसाय के रूप में संचालित है। रेशम की तीन वाणिज्यिक किस्मों टसर, शहतूती एवं ईरी रेशम के उत्पादन का गौरव प्राप्त छत्तीसगढ़ टसर कोसा उत्पादन में अग्रणी हैं, बावजूद इसके उद्योग की गणना पिछड़े उद्योगो में की जाती है, जिसका प्रमुख कारण उद्योग की विशिष्ट समस्याएं है, जिसमें प्रमुख समस्या हितग्राहियों की आय का न्यून होना है।

6. आर्थिक सर्वेक्षण, छत्तीसगढ़ शासन (2013) कृषि एवं संबंध सेवाएं पृष्ठ–38
7. http://indianexpress.com/article/business/economy/poverty-count-chhattisgarh-worst-off-orissa-and-mp-follow/
8. http://www/csb.gov.in/assets/.../AR-0910en.pd/...silk.
9. http://www/csb.gov.in/assets/.../AR-0910en.pd/...silk.

अतः प्रस्तुत शोध पत्र में टसर कोसा उत्पादन एवं उत्पादन में संलग्न हितग्राहियों की आय का अध्ययन कर इसके न्यूनता के कारणों को रेखाकिंत करना तथा गैर कृषि क्षेत्र में उद्योग द्वारा रोजगार सृजन की संभावनाओं का अध्ययन कर उपयुक्त सुझाव प्रस्तुत करना है।

शोध प्राविधि :–

प्रस्तुत शोध सविचार निर्देशन एवं द्वितीयक आंकड़ो पर आधारित है अध्ययन का क्षेत्र संपूर्ण छत्तीसगढ़ है तथा राज्य में उत्पादित रेशम की तीन किस्मों में से टसर कोसा उत्पादन को अध्ययन हेतु चुना गया है। साथ ही उत्पादन एवं संलग्न हितग्रहियो के अध्ययन हेतु 13 वर्ष अर्थात 2000–01 से 2012–13 अवधि के आंकड़ो को लिया गया है। किंतु आवश्यक एवं प्रासंगिक होने पर इसके पूर्व एवं बाद की भी जानकारी ली गई हैं, जबकि गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार संबंधी स्थिति के अध्ययन हेतु शोधपत्रो एवं NSS द्वारा प्रकाशित आकड़ों का प्रयोग किया गया है,

उद्देश्य :–

1. भारत तथा छत्तीसगढ़ के गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार की स्थिति का अध्ययन करना है।
2. छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना वर्ष 2000 से 2013 तक की अवधि में टसर कोसा उत्पादन की स्थिति का अध्ययन करना है।
3. एवं उक्त अवधि में टसर कोसा उत्पादन में संलग्न हितगग्राहियों की संख्या एवं आय संरचना का अध्ययन करना हैं।

वर्ल्ड वॉच इंस्टीयूट के अनुसार 1980 और 2011 के बीच भारत के कृषि आश्रित जनसंख्या में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जो कृषि प्रधान अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक है।[12] इस रिपोर्ट को यदि अन्य अध्ययनों के साथ मिला कर देखें तो बड़ी चिंताजनक तस्वीर उभरती है। एक ओर खेती पर लोगो का भार बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर G.D.P. में खेती का योगदान गिरकर न्यूनतम स्तर पर आ गया है।

10. आर्थिक सर्वेक्षण, छत्तीसगढ़ शासन (2013) ग्रामोद्योग रेशम प्रभाग, पृष्ठ–83

11 http:www/btsso.gov.in

12. कुमार, ए. (2014 मार्च) 'कृषि पर निर्भरता' बिलासपुर संस्करण हरिभूमि पृष्ठ –6

पिछले कुछ वर्षो में कृषि की औसत संवृद्धि दर **2.5%**[13] से भी कम दर्ज की गई है। कृषि विकास के गिरते ग्राफ एवं आर्थिक विकास की धीमी रफ्तार ने ग्रामीण क्षेत्रो में बेरोजगार जनाधिक्य की बढ़ती जमात के लिए रोजगार अवसर पैदा करने में बहुत बाधा पहुंचाई है, जिसका गंभीर दबाव खेती पर पड़ा है, इस संबंध में यह कहा जा रहा है कि कृषि उत्पादकता एवं आर्थिकी को बेहतर करने की कोशिशों के रूप में गैर कृषि क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।

national sample survey (NSS) के 38 वें, 50 वें, 61 वें एवं 66 वें चक्र के आकड़ें यह बताते है कि भारत में गैर कृषि क्षेत्र की सहभागिता ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्धता की दृष्टि से बेहतर हुई है, जिसे महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में देखा जा रहा है।

तालिका क्र.–1

गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार

(छत्तीसगढ़ के संदर्भ में)

राज्य	1983	1993-94	2004-05	2009-10
आंध्र प्रदेश	20.0	22.7	28.3	31.3
आसाम	21.0	21.3	25.8	29.5
बिहार	15.6	16.9	22.1	33.1
छत्तीसगढ़	**7.0**	**9.4**	**13.9**	**15.1**
गुजरात	15.2	20.7	22.8	21.7
हरियाणा	23.1	28.6	36.0	40.2
हिमाचल प्रदेश	12.9	22.8	30.6	37.1
जम्मू–कश्मीर	20.3	28.0	36.2	40.3
झारखंड	18.6	23.9	30.1	45.2
कर्नाटक	15.7	18.3	19.1	24.3
केरल	37.2	42.3	58.0	64.3
मध्यप्रदेश	11.0	13.8	17.5	17.6
महाराष्ट्र	14.3	20.3	20.1	20.6
उड़ीसा	20.9	21.9	31.0	32.4
पंजाब	17.8	22.7	33.2	38.2
राजस्थान	13.5	19.2	27.2	36.7
तमिलनाडू	25.6	31.3	34.7	36.3
उत्तर प्रदेश	17.9	20.7	27.4	33.1
उत्तराखंड	18.1	34.9	21.8	30.5
पश्चिम बंगाल	26.4	26.9	37.3	43.7
अखिल भारत	18.6	21.7	27.4	32.1

स्त्रोत :– Economic and political weekly (2014 march15) Vol-52,p.45-48

गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार

(छत्तीसगढ़ के संदर्भ में)

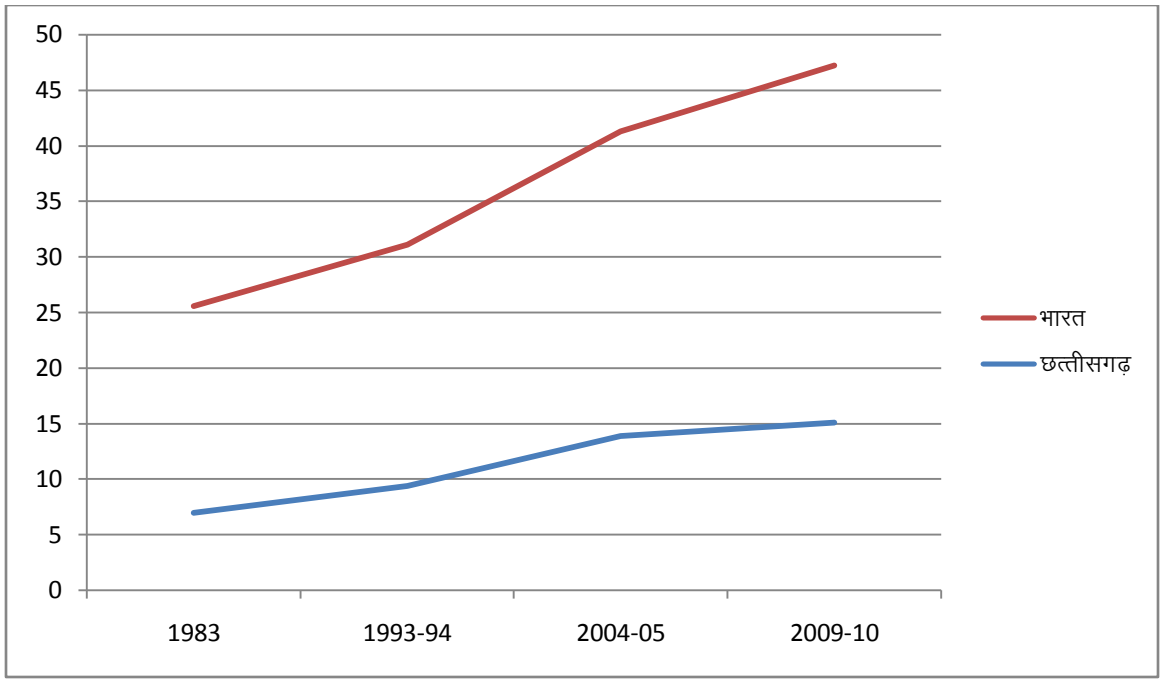

तालिका क्र. 1 के विश्लेषणात्मक अध्ययन से ज्ञात होता है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रो में अतिरिक्त रोजगार का सृजन गैर कृषि क्षेत्रों जैसे मत्स्यपालन , रेशम उत्पादन, बागवानी डेयरी फार्म में ही हो रहा है। 1983 और 1993–94 में 47 मिलियन अतिरिक्त ग्रामीण रोजगार सृजन गैर कृषि क्षेत्रों में हुआ । **वर्तमान में 10 में से 6 व्यक्ति गैर कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। 1993–94 और 2004–05 में गैर कृषि क्षेत्रो में रोजगार सृजन की वृद्धि कृषि क्षेत्रो से भी आगे बढ़ गई तथा 50 मिलियन नए रोजगार अवसरों का सृजन गैर कृषि क्षेत्रों में हुआ, यद्यपि विगत वर्ष 2004–05 और 2009–10 में कुल ग्रामीण रोजगार में 5 मिलियन की गिरावट आई है, बावजूद इसके किन्तु उक्त अवधि में 13 मिलियन ग्रामीण रोजगार पैदा करने में गैर कृषि क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।**[14] । इस नजरिये से जहां भारत के कुछ राज्यों में गैर कृषि क्षेत्रो का प्रदर्शन बेहतर रहा, वही कुछ राज्यो की स्थिति कमजोर पायी गई, जिसमें छत्तीसगढ़ की स्थिति सभी राज्यो की तुलना में निम्न रही। (तालिका क्रमांक 1) कम 7.0% है, यद्यपि वर्ष 2009–10 की अवधि तक यह सहभागिता 15.1 प्रतिशत के स्तर पहुंच गई है,

Geetanjali K. (2014) Rural Non-form employment in India. *Ecomomic and Political Weekly Vol-52 P.45-48*

किन्तु फिर भी न केवल यह तालिका क्रमांक 1 में दिये गए राज्यों से काफी पीछे है, बल्कि राष्ट्रीय औसत 32.1 से भी काफी दूर है। स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि कृषि की दयनीय स्थिति एवं गैर कृषि

क्षेत्र द्वारा रोजगार सृजन की धीमी गति राज्य में व्यापक स्तर पर प्रवास एवं ग्रामीण निर्धनता हेतु जिम्मेदार है।

तालिका क्र. –2

छत्तीसगढ़ राज्य में टसर कोसा उत्पादन
(2000–01 से 2012 –13 की अवधि में)

(लाख नग में)

क्र.	वर्ष	पालित	नैसर्गिक	कुल कोसा उत्पादन	प्रतिशत वृद्धि (%में)
1.	2000-01	5912000	49600000	55512000	-
2.	2001-02	17242000	57042000	74284000	33.81
3.	2002-03	23800000	38271000	62071000	-16.4
4.	2003-04	21860300	82879300	104739600	68.74
5.	2004-05	31096100	75816400	106912500	2.07
6.	2005-06	33051184	37886905	177850589	66.35
7.	2006-07	38622208	50605200	89227408	-49.83
8.	2007-08	45710097	58674200	104384297	16.98
9.	2008-09	43498788	75451966	223335051	113.95
10.	2009-10	43869200	80915800	124785000	-44.13
11.	2010-11	41896780	87007800	128904580	3.30
12.	2011-12	52404990	163626895	216031885	67.59
13.	2012-13	56601390	199977402	256578792	18.76
योग	-	408611037	1057754868	1724616702	-
औसत	-	31431618.2307	81365759.07	132662823.23	-

स्त्रोत :– ग्रामोद्योग (रेशम प्रभाग) संचालनालय रायपुर, छत्तीसगढ़

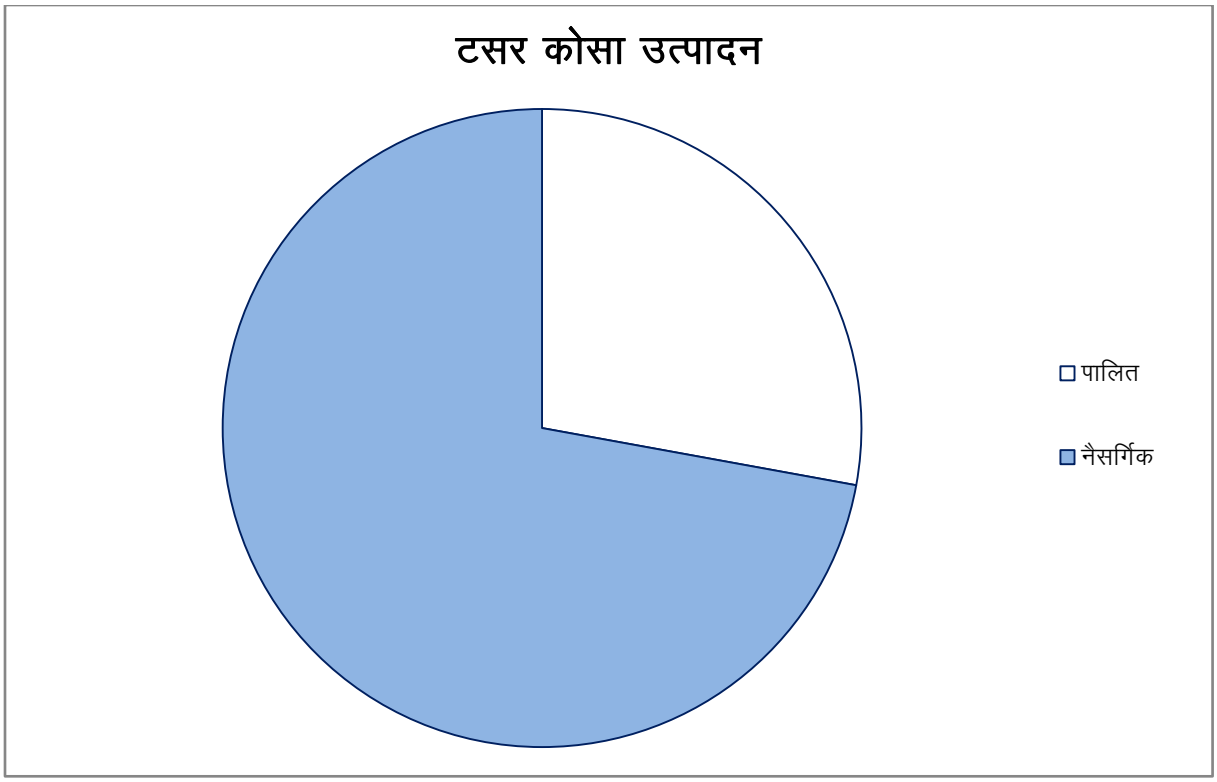
टसर कोसा उत्पादन
पालित
नैसर्गिक

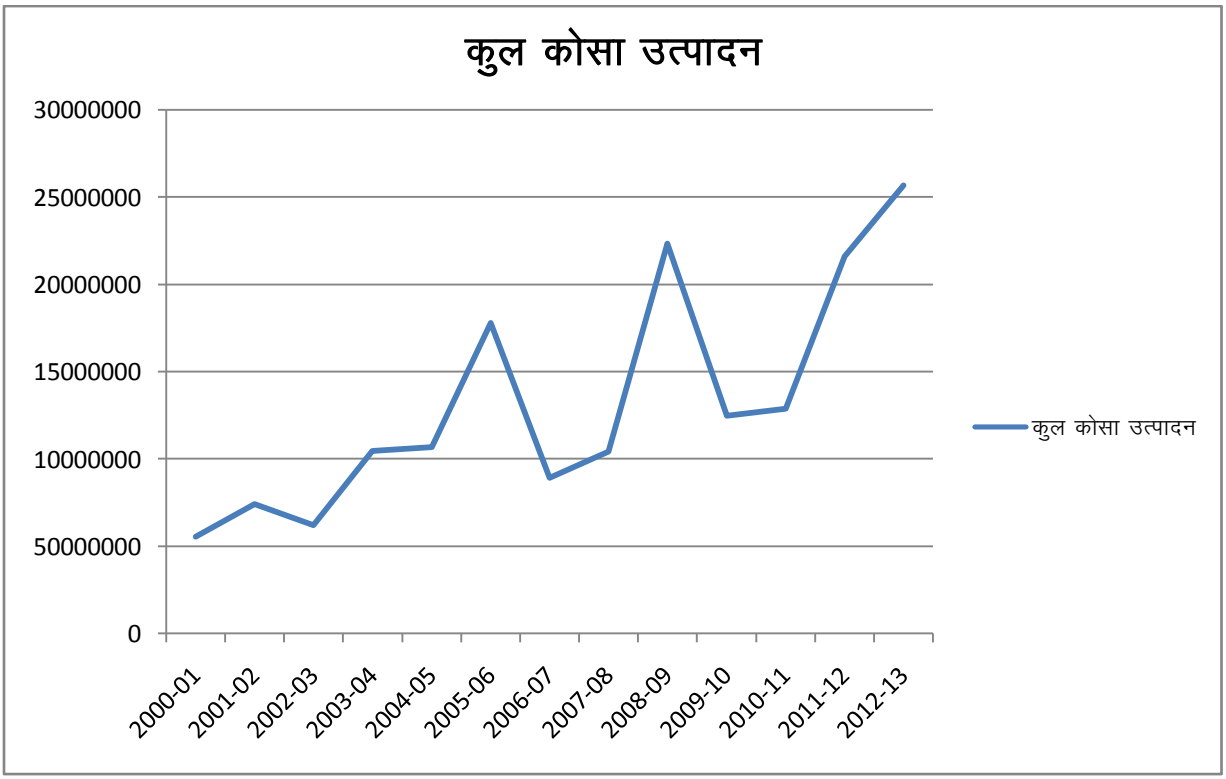
कुल कोसा उत्पादन
30000000
25000000
20000000
15000000
10000000
50000000
0
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
कुल कोसा उत्पादन

भारत के कुल टसर रेशम उत्पादन में 22.38 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ छत्तीसगढ़ का स्थान द्वितीय है। अध्ययन वर्ष 2000–01 से 2012–13 की अवधि में कुछ वर्षो को छोड़कर टसर कोसा उत्पादन की स्थिति अच्छी रही है किन्तु इसे संतोषजनक नही माना जा सकता है। क्योंकि उत्पादन में वृद्धि न केवल लक्ष्य से सदैव कम रही है, बल्कि कुछ वर्षो में यह वृद्धि ऋणात्मक भी रही है। कुल टसर कोसा उत्पादन में नैसर्गिक (रैली) कोसा उत्पादन का हिस्सा अधिकतम रहा हैं जो उक्त अवधि में औसतन 81365759.07 लाख नग रहा, जबकि पालित टसर कोसा उत्पादन 31431618.2307 लाख नग रहा। पालित टसर कोसा उत्पादन के कम होने का मुख्य कारण रेशम कृमियों को लगने वाली बिमारियां, मौसम की प्रतिकूलता एवं इनके रखरखाव के सम्बंध में किसानो की अनभिज्ञता है, जबकि नैसर्गिक टसर कोसा उत्पादन के अधिक होने का कारण वनों की अधिकता तथा अर्जुन, साजा वृक्षो का बहुतायात से पाया जाना है। प्राचीन काल से राज्य के आदिवासियों के जीवनयापिका एवं आय का मुख्य स्त्रोत टसर कोसा (नैसर्गिक) उत्पादन रहा है। परम्परागत रूप से उत्पादन से जुड़े होने के कारण आदिवासी टसर कोसा उत्पादन में कुशल तो है, परंतु अशिक्षा एवं वैज्ञानिक ज्ञान के सम्बंध में अनभिज्ञता जहां इनकी बिचौलियों के द्वारा शोषण का कारण रही, वही दूसरी ओर उत्पादन में उतार–चढ़ाव की प्रवृत्ति एवं गुणवत्ता युक्त ककून का सीमित उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से हितग्राहियो की आय एवं संख्या की वृद्धि के मार्ग में बाधक भी रही है।

तालिका क्र. –3

छत्तीसगढ़ राज्य मे टसर कोसा उत्पादन में संलग्न हितग्राहियो की संख्या एवं प्रति हितग्राही आय
(2000–01 से 2012–13 की अवधि में)

क्र	वर्ष	टसर कोसा उत्पादन के विभिन्न कार्यो में संलग्न हितग्राहियों कि संख्या				कुल हितग्राही	प्रतिशत वृद्धि	प्रति हितग्राही आय	प्रतिशत वृद्धि
		पालित	नैसर्गिक	धागाकरण	टसर पौधरोपण		(% में)	स्पये में	(% में)
1.	2000-01	4965	26757	80	3104	34906	-	1512	-
2.	2001-02	6811	17235	129	-	24175	-30.74	2981	97.15
3.	2002-03	8430	20142	111	-	28683	18.64	2096	-29.68
4.	2003-04	9414	35752	703	1043	46912	63.55	2237	6.72
5.	2004-05	12145	57218	958	2395	72716	55.00	1487	-33.52
6.	2005-06	11859	36759	723	3006	52347	-28.01	3530	137.39
7.	2006-07	13029	41577	1458	2430	58494	11.74	1658	-53.03
8.	2007-08	15107	42043	1113	4524	62787	7.33	1854	11.82
9.	2008-09	11160	43761	843	6211	61975	-1.29	4127	122.59
10.	2009-10	10188	44276	582	6538	61584	-0.63	2863	-30.62
11.	2010-11	9417	38802	802	7904	56925	-7.56	3341	16.69

12.	2011-12	10457	52366	713	5792	69328	21.79	5158	54.38
13.	2012-13	11335	62869	1108	8429	83741	20.78	5532	7.25
योग		134317	519557	9323	51376	714573	-	38376	-
औसत		10332.07	39965.92	717.15	3952	54967.15	-	2952	-

स्त्रोत :– ग्रामोद्योग (रेशम प्रभाग) संचालनालय रायपुर, छत्तीसगढ़

टीप :– अध्ययन में चूकिं मात्र टसर कोसा उत्पादन को लिया गया है, अतः प्रति हितग्राही आय की गणना में केवल पालित एवं नैसर्गिक कोसा उत्पादन में संलग्न हितग्राहियों को शामिल किया गया है।

टसर कोसा उत्पादन के विभिन्न कार्यो में संलग्न हितग्राहियों कि संख्या

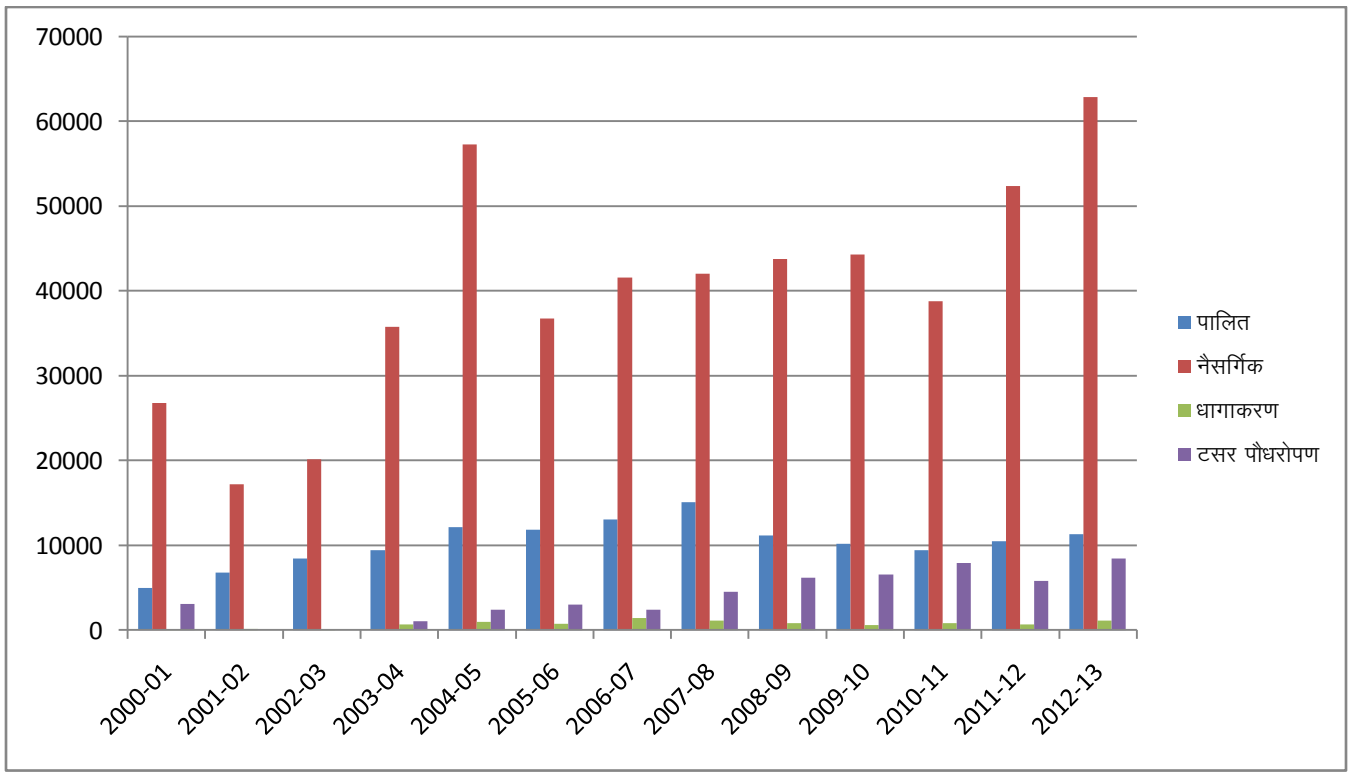

टसर कोसा उत्पादन में हितग्राहियों की संख्या एवं प्रति हितग्राही आय

तालिका क्र. 3 के विश्लेषणात्मक अध्ययन से ज्ञात होता हैकि राज्य निर्माण वर्ष 2000–01 से 2012 –13 की अवधि तक टसर कोसा उत्पादन में संलग्न हितग्राहियों की कुल संख्या मात्र 714573 रही है। प्रतिवर्ष हितग्राहियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि के आधार पर कहा जा सकता है कि न केवल इनकी संख्या में वृद्धि काफी धीमी रही है, बल्कि कुछ वर्षों में यह वृद्धि ऋणात्मक भी दर्ज की गई है, जिसका मुख्य कारण अर्जित आय का अत्याधिक कम या अपेक्षित आय का न प्राप्त होना है। ज्ञातव्य हो कि रेशम उद्योग में धागाकरण का कार्य मुख्य रूप से महिला हितग्राहियों द्वारा किया जाता है, जिसमें उन्हें प्रति हितग्राही 1500–2000 रूपये प्रतिमाह की आय प्राप्त होती है, जबकि टसर पौधरोपण हेतु खुदाई, बुवाई जैसे कार्य श्रामिकों द्वारा किए जाते है, जिन्हे निर्धारित मजदूरी के अनुसार भुगतान किया जाता है।

उपरोक्त दिए गए विश्लेषण को मिलाकर देखा जाए तो ज्ञात होता है कि रेशम उद्योग में न केवल पुरूषों, अपितु महिलाओं एवं वृद्धों को स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भर बनाने की भी असीम क्षमता एवं संभावनाएं मौजूद है। किन्तु रेशम कृमि को लगने वाली बिमारियां, स्वास्थ्य खाद्य वृक्षों की कमी एवं वैज्ञानिक ज्ञान के अभाव ने जहां उत्पादन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है, वही उत्पादन में होने वाली धीमी एवं ऋणात्मक वृद्धि तथा उत्पादको में सौदा करने की क्षमता का अभाव जैसी प्रवृत्तियों ने हितग्राहियों की संख्या एवं आय को निम्न स्तर पर ही बना रखा है। परिणामतः प्रदेश में टसर कोसा उत्पादन हेतु अनुकूल दशाओ की विद्यमानता के बावजुद यह उद्योग पिछड़े उद्योगो में शामिल है, एवं गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार एवं आय पैदा करने में स्वयं को मजबूती से स्थापित करने में असफल रहा है। रेशम उद्योग हेतु शासन की नीतियों का प्रभावपूर्ण रूप से लागू न होना, बिचौलियों एवं बाहरी व्यापारियों द्वारा किसानों एवं आदिवासियों का शोषण ऐंसे कारण हैं जो हितग्राहियों की आय की अनियमितता एवं उत्पादन में उतार

चढ़ाव हेतु उत्तरदायी है। भारतीय रेशम उद्योग की अपनी कुछ विशिष्ठ समस्याएं है। स्वाभाविक तौर पर छत्तीसगढ़ रेशम उद्योग उससे परे नही है। प्रदेश में रेशम उद्योग की घरेलू एवं निर्यात बाजार की परिवर्तित आवश्यकताओं के अनुरूप बर्ताव एवं ग्रहण क्षमता की असमर्थता तो दूसरी तरफ इस दिशा में शोध एवं विकास हेतु शासन की नीतियों का प्रभावपूर्ण ढंग से लागू न होना, मध्यस्थों की उपस्थिति आदि इस उद्योग की गंभीर
समस्याओं में सें है।

निष्कर्ष :–

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में रेशम उद्योग कृषि के सहायक व्यवसाय तथा गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार सृजन कि दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में टसर कोसा उत्पादन संबंधी गतिविधियाँ गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार एवं अतिरिक्त आय सृजन के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती है। प्रदेश में उद्योग के स्थानीयकरण एवं अनुकूल दशाओं की विद्यमानता इसकी विकास की संभावनाओ को उत्साहजनक बता रही है। अतः जरूरत इस बात की है कि टसर कोसा उत्पादन में वृद्धि हेतु अतिरिक्त तकनीकी एवं सफल शोधों की दिशा में प्रभावी ढ़ंग से सोचा जाए। इस संदर्भ में राज्य सरकार को अपनी योजनाओं एवं नीतियों का मूल्यांकन कर नये सिरे से क्रियान्वयन करने एवं उद्योग की विशिष्ट समस्याओं के विषय में जमीनी स्तर से विचार करने की आवश्यकता है।

सुझाव एवं अनुशंसा :–

यद्यपि गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार सृजन की दृष्टि से अन्य कई व्यवसाय महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे है, किंतु टसर कोसा उत्पादन हेतु छत्तीसगढ़ में अनुकूल दशाओं की विद्यमानता ने इसकी विकास की संभावनाओं को काफी महत्वपूर्ण बना दिया है। पूर्णतया श्रम आधारित रेशम उत्पादन गतिविधियाँ ग्रामीण क्षेत्रो में मौजूद निष्क्रिय श्रम को रोजगार देने एवं अदृश्य बेरोजगारी जैसी गंभीर समस्या के निदान में काफी सहायक सिद्ध हो सकती है, किन्तु रेशम उत्पादन हेतु शासन की नीतियों का प्रभावपूर्ण ढंग से लागू न होना एवं उत्पादकों में जागरूकता, वैज्ञानिक ज्ञान के अभाव के परिणामस्वरूप लाभ का बहुत कम भाग उन तक पहुँच पाता है, अर्थात उत्पादन के प्रारंभिक स्तर से जुड़े हितग्राहियों जैसे किसानों, कृमिपालकों, बुनकर उस लाभ से वंचित है जो उन्हें वास्तविक रूप मे मिलना चाहिए, वही दूसरी ओर रेशम कृमि को लगने वाली बिमारियां एवं मौसम की प्रतिकुलता जैसी स्थिति में फसल खराब हो जाने की संभावना के कारण कृषक स्वयं को इस व्यवसाय से जोड़ने में काफी जोखिम महसूस कर रहे है। अतः
शासन की नीतियों में रेशम उद्योग हेतु विशेष प्रावधान जैसे उद्योग हेतु बिजली, पानी की सुविधा, कम दरों

पर ऋणों की उपलब्धि, उत्पादन के प्रारंभिक स्तर से जुड़े उत्पादकों को बीमा जैसी सुविधा मुहैया कराना ना केवल आवश्यक है बल्कि इन नीतियों का क्रियान्वयन जमीनी स्तर से किया जाना जरूरी है।

हितग्राहियों को जागरूक एवं प्रशिक्षित कर उनमें सौदा करने की क्षमता पैदा करना। उत्पादन की परम्परागत पद्धति एवं नवीन तकनीकी के मध्य अंतराल को शोध एवं विकास द्वारा ही पाटा जा सकता है। हितग्राहियों के चयन के मानक में परिवर्तन करने के साथ, प्रति हेक्टेयर टसर पौधो की संख्या एवं पौधो के बीच की दूरी एवं रेशम कृमियों को बिमारी से बचाव हेतु वैज्ञानिक जानकारी देने जैसे उपाय टसर कोसा उत्पादन में इजाफा, हितग्राहियों की संख्या एवं आय वृद्धि की दृष्टि से महत्वपूर्ण तो होंगें साथ ही छत्तीसगढ़ गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार सृजन कर कृषि पर बढ रहे दबाव को कम कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में अपनी प्रभावी सहभागिता को दर्ज करा पायेगें।

✧ ✧ ✧

संदर्भ सूची

शोध पत्र

- HANUMANTHAPPA K.(2012) POVERTY RURAL INDEBTEDNESS AND FARM DISTRESS:AN ANAIYSIS. *SOUTHERN ECONOMIST VOL-50 P.47-48*
- SATYANARAYANA G., ANDRAJU G.AND SAMPANGI RAMAIAH P.N.(2012) NON FARM SECTOR IN RURAL DEVELOPMENT WITH REFERENCES TO HANDLOOM INDUSTRY IN ANANTAPUR. *SOUTHERN ECONOMIST VOL-50 P.43-44*
- HANUMANTHAPPA K.(2012) POVERTY DISABILITY, RURAL MARKETING AND AGRAIAN DISTRESS IN INDIA. *SOUTHERN ECONOMIST VOL-51 P.19-20*
- MUNIRAJU M. AND SRINIVASA A.T.(2012) POPULATION GROWTH AND CHANGING AGRARIAN RELATIONSHIP . *SOUTHEN ECONOMIST VOL—51 P.50-56*
- RAHMATULLA M.(2012)THE U.S. RECESSION AND EMPLOYMENT IN INDIA. *SOUTHERN ECONOMIST VOL-51 P.10-14*
- REDDY B. A. K. AND DESAI K.(2012)GLOBALISATION AND POVERTY ANALYSIS IN INDIA. *SOUTHERN ECONOMIST VOL-51 P.34-39.*

- RAVI KUMAR S. AND RAJASHEKHAR D.(2012) ROLE OF SMALL SCALE INDUSTRIES IN TAMILNADU. *SOUTHERN ECONOMIST VOL-51 P.7-10*
- TANKASALI S.G. AND HUNDEKAR S.G.(2012) MULBERRY PRODUCTION IN INDIA UNDER GLOBAL ENVIRONMENT- A SWOT ANALYSIS CONDUCTED AT KARNATAKA. *SOUTHERN ECONOMIST VOL-51 P.41-48*
- Raja Justus e.and koli samuel G.(2013) land utilization irrigation and crop development:A study southern ECONOMIST vol- 51 P.21-22
- SHEJAL S.S.(2013) RURAL INDUSTRIALISATION IN SANGLI DISTRICT. *SOUTHERN ECONOMIST VOL-52 P.9-10*
- PANDEY M. AND C. OJHA (2013) IMPACT OF ECONOMIC GROWTH ON EMPLOYMENT IN INDIA. *SOUTHERN ECONOMIST VOL-52 P.-19*
- GUPTA E.A.P AND SATHEESH K.G(2013) GLOBAL AND INDIAN MILK PRODUCTION. AND CONSUMPTION SCENARIO. *SOUTHERN ECONOMIST VOL- 51 P.11-12*
- MOHAN I.M. AND SAVITHRI H.E.(2013) SMALL SCALE INDUSTRIES IN INDIA DURING FIVE YEAR PLANS. *SOUTHERN ECONOMIST VOL- 52P.5-6*
- MATHEW L. AND THOMAS T.(2013) INCLUSIVE GROWTH IN THE POST REFORM PERIOD IN INDIA WITH SPECIAL REFRENCE TO AGRICULTURE . *SOUTHERN ECONOMIST VOL-51 P.41-42SA*
- RAMALINGAIAK L(2013) SOCIO ECONOMIC STATUS OF CATTLE FARMERS IN MANDYA. *SOUTHERN ECONOMIST.VOL-51 P.51-54*
- KIRUTHIGA S. AND CHITHRA N. (2013) TRIBAL ECONOMY OF INDIA WITH SPECIAL REFRENCE TO TIRUCHIRAPALLI DISTRICT OF TAMILNADU. *SOUTHERN ECONOMIST VOL-52 P.5-8*
- MATHEW G.(2013) EFFICASY OF SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT IN KERLA. SOUTHERN ECONOMIST. *SOUTHERN ECONOMIST VOL-52 P.27-30*.
- VENKATACHALAM C. AND SUBBA REDDY S.V.(2013) ECONOMICS OF SERICULTURE-A MICRO LEVEL STUDY. *SOUTHERN ECONOMIST VOL-52 P.33-37*

- LALRINFELI (2013) SILK WARM PRODUCTION AND ITS EMPLOYMENT POTENTIAL IN THE FARM ECONOMY OF MIZORAM. *SOUTHERN ECONOMY VOL-51 P.45-50*
- KOMARASAMY P. AND MANIVANNA L.(2013) SOCIO ECONOMIC FACTORES OF POWERLOOM OWNERS IN ERODE. *SOUTHERN ECONOMIST VOL-51 P.41-45*.
- RATHEESH C. AND JOHN P.(2013) COMPARATIVE ANALYSIS OF PRE AND POST REFORM AGRICULTURE CREDIT AND CAPITAL FORMULATION. *SOUTHERN ECONOMIST VOL-51 P.49-54.*
- SUNDRAM I.S. (2013) DIMENSIONS OF AGRARIAN DISTRESS IN INDIA. *SOUTHERN ECONOMIST VOL-51 P.56-61*.
- RATHEESH C.AND LEGIO MERIL D.(2014) IMP ACT OF RURAL LABOUR MARKET CHANGES ON CROPING PATTERN IN KERLA *SOUTHERN ECONMIST VOL* 53P.5-6
- MAHADESH K.C.(2014) ROLE OF KHADI AND COTTAGE INDUSTRIES IN INDIA SOUTHEN ECONOMIST VOL-53 P.23-24
- SUNEETA M.(2014) FEMALE LABOUR PARTICIPATION AGRICULTURE: A CASE OF ANDHRA PRADESH. *SOUTHERN ECONOMIST VOL-52 P.46-47*
- JEEVAN KUMAR D.(2014) THE GANDHIAN VISION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT. *SOUTHERN ECONOMIST VOL-53 P.43-47*
- GEETANJALI K.(2014) RURAL NON FARM EMPLOYMENT IN INDIA. *SOUTHERN ECONOMIST VOL-52 P.*
- EKAMBARAM K.(2014) PERFORMANCE OF KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES IN INDIA. *SOUTHERN ECONOMIST VOL-52 P.5-8*
- RanawareK. ,DAS U.,KULKARNI A.,NARAYANA S (2015) MGNREA WORKS AND THEIR IMPACT A STUDY OF MAHARASHTRA. *ECONOMIC AND POLITICAL WEEKLY MARCH 28 VOL NO-13P.53-54*

पुस्तकें

- SAHOO B.(1993).PROBLEM AND PROSPECTS OF TEXTILE INDUSTRY. *NEW DELHI: MITTAL PUBLICATION.*
- MILAN(2006).TEXTTILE INDUSTRY OF INDIA AND PAKISTAN. *NEWDELHI:APH PUBLISHING CORPORATION.*
- RAJENDRA KUMAR C.(2008).RESEARCH METHODOLOGY. *NEW DELHI: APH PUBLISHING CORPORATION.*

रिपोर्ट

- REPORT ON EMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENT SURVEY(2009-10).LABOUR BUREAU.MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT.*GOVT. OF INDIA.*
- REPORT OF THE WORKING GROUP ON TEXTILES AND JUTE INDUSTRY FOR THE ELEVENTH FIVE YEAR PLAN(2007-2012*) GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF TEXTILES.*
- CENTRAL SILK BOARD VANYA SILK DIRECTORY(2013). *MINISTRY OF TEXTILES. GOVT OF INDIA.*

समाचार पत्र

- News paper-times of India.indiatimes.com/India/mass-exodus-100000-villagers-migrate-.,from-chhattisgarh-in-3 years/ article show /46818527

Electronic Documents

- http://www.csb.gov.in/silk-sericulture/sericulture/
- www.CSB.gov.in/stastics/silk/-bulletin/
- www.CSB.gov.in/stastics/silk-exports and imports.
- WWW.CSB.gov.in/stastics/silk-exports-and-imports/countrywise-import/
- www.CSB.gov.in/silk-sericulture/silks-of-india.
- PIB.nic in/archieve/others/2012/mar/d2012031302 pdf
- http://WWW.googal.co.in/webhp-source=search-app&gfe-rd=cr&ei=iknguf-exvv8gfjjocica #q=cottage+industries.